

भाजपा राहुल गांधी को घेरने की फिराक में है

पर, पार्टी में मतभेद हैं कि राहुल को पुनः संसद से “डिस्क्वालिफाई” करा दिया जाता है तो वे “हीरो” के रूप में उभर सकते हैं तथा जनता में उनके प्रति सहानुभूति उभरेगी

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 11 फरवरी। भाजपा ने राहुल गांधी को घेरने के लिए कमर कस ली है, और उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रियों के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और उसे लेकर भाजपा कार्रवाई करना चाहती है।

यह अवसर आज तब आया, जब बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने मंत्री हरदीप पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम एप्स्टिन फाइल्स में शामिल होने के संबंध में लिया।

इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी पर दबाव था, क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका की अदालतों में एक मामला चल रहा था, और चूंकि अडानी मोदी के वित्तीय सहयोगी और आर्किटेक्ट हैं, इसलिए प्रधानमंत्री पर दबाव था और उन्होंने भारत-अमेरिका ट्रेड डील के मामले में

- पर, दूसरी सोच यह है कि राहुल गांधी को सबक सिखाना जरूरी है तथा अगर भाजपा से नज़दीकी रखने वाले चुनाव आयुक्त हों तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव छः महीने नहीं होने दे।
- पर, बहरहाल अभी तो इस बात पर भाजपा में आम सहमति बनी है कि राहुल गांधी के खिलाफ सदन में “प्रिविलेज” प्रस्ताव तो लाया ही जाए, जिस तरह बजट पर बोलते हुए उन्होंने मंत्री हरदीप पुरी व बिज़नैसमैन अनिल अंबानी पर लांछन लगाया कि उनके नाम “एप्स्टिन फाइल्स” में आये हैं।
- भाजपा, इस बात से भी काफी उत्तेजित है कि जिस तरह राहुल गांधी ने प्र.मंत्री पर कई आरोप लगाए, अमेरिका के सामने आत्म समर्पण किया। पर, दुविधा यह है कि भाजपा निश्चित नहीं कर पा रही है कि राहुल गांधी से किस तरह डील किया जाए।

ट्रम्प के सामने समर्पण कर दिया। सूत्रों का कहना है कि एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है। सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार और भाजपा में इस पर मतभेद है कि क्या राहुल गांधी को सदन की सदस्यता

के अयोग्य ठहराने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। एक गुट का मानना है कि यह कदम अक्लमंदी नहीं होगा, क्योंकि इससे राहुल गांधी एक “हीरो” बन जाएंगे तथा और अधिक लोग उनके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे। दूसरा गुट, जो सख्त रुख अपनाए हुए है, उसका कहना है कि राहुल गांधी को सबक सिखाना चाहिए। यदि उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है, तो सरकार का आज्ञाकारी चुनाव आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव 6 महीने से पहले नहीं कराए जाएं। लेकिन वे राहुल गांधी को अपमानित करने के लिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना चाहते हैं। राहुल गांधी के मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ तीखे शब्दों ने सरकार को आहत किया है, लेकिन सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी के साथ क्या किया जाए, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य के आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता’

नई दिल्ली, 11 फरवरी। केन्द्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य आधार पर डिटेंशन से रिहा नहीं किया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ को बताया कि अदालत के अनुरोध पर स्वास्थ्य आधार पर डिटेंशन को समीक्षा के लिए गंभीरता से विचार किया गया, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सका। मेहता ने कहा कि जेल मेनुअल के अनुसार, वांगचुक की 28 बार चिकित्सकीय जांच की गई है और वे स्वस्थ, ठीक-

- केन्द्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया।

ठाक और सामान्य हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ पाचन संबंधी समस्या हुई थी, जिसका इलाज चल रहा है और कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। पिछली सुनवाई में जस्टिस वराले ने मौखिक रूप से वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति पर चिंता जताई थी और डिटेंशन पर पुनर्विचार का सुझाव दिया था, जिस पर न्यायमूर्ति कुमार ने भी सहमति व्यक्त की थी। पीठ ने यह भी टिप्पणी की थी कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें केंद्र सरकार वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को पूरी तरह नकार रही हो।

‘राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के सभी 6 अंतरे बजाना अनिवार्य होगा’

केन्द्र सरकार ने स्कूलों व सरकारी कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया

- केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रगीत वंदे मातरम् , राष्ट्रगान जन गण मन से पहले बजाया जाएगा। सिनेमा घरों में भी गीत बजाया जाएगा, पर, इसके लिए खड़े होना अनिवार्य नहीं है।
- ज्ञातव्य है कि कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 में वंदे मातरम् को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया था, तब इसके तीन अंतरे ही मंजूर किए थे। बाद के तीन अंतरे छोड़ दिए गए थे, जिनमें हिंदू देवी मां दुर्गा की वंदना की गई थी।
- यह गीत 7 नवम्बर 1875 में लिखा गया था, गत वर्ष नवम्बर में इसकी 150वीं जयन्ती पर संसद का विशेष सत्र बुलाकर भाजपा ने कांग्रेस पर सांभ्रादयिक आधार पर गीत को विभाजित करने का आरोप लगाया था।

अन्तरों को अपनाया गया था, ताकि कथित तौर पर, गीत की धर्मनिरपेक्ष अपील बनी रहे। देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा देने और देश की धरोहर पर पुनः दावा करने के अपने प्रयासों के तहत, एनडीए सरकार गीत को वह महत्व देने की कोशिश कर रही है, जिसके योग्य

‘डॉक्टर्स को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से बाहर रखा जाए’

एक जनहित याचिका में की गई इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से जवाब मांगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 11 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को, एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया तथा जवाब मांगा यह याचिका हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (इंडिया) एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है, जिसमें 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत चिकित्सा पेशेवरों को बाहर करने की मांग की गई है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून, जो मरीजों को उपभोक्ता अदालतों में दावा करने की शक्ति देता है, चिकित्सा तापरवाही के लिए हर्जाना मांगने का अधिकार प्रदान करता है, और इसमें चिकित्सा पेशेवरों को शामिल करना

- सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स द्वारा दायर जनहित याचिका पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
- उपभोक्ता/संरक्षण कानून में चिकित्सा सेवा को भी शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के एक फैसले में कहा था कि अगर डॉक्टर निःशुल्क सेवा नहीं दे रहे हों तो उनके द्वारा दिया गया इलाज उपभोक्ता सेवा के दायरे में ही आता है।

“डॉक्टर-पेशेंट रिश्ते के विश्वास को कमजोर करता है और चिकित्सा प्रैक्टिस की नैतिक नींव को नष्ट करता है।” मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एनबी अंजारिया की पीठ ने हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (इंडिया) एसोसिएशन (एएचपी) और इसके पूर्व अध्यक्ष, बेंगलुरु के एक डॉक्टर द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि चिकित्सा सेवाओं पर उपभोक्ता कानून लागू करने से चिकित्सा प्रैक्टिस में रक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। इसमें कहा गया है कि चिकित्सा लापरवाही की जांच करने के लिए अन्य, अधिक उपयुक्त तंत्र हैं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘तीन साल से एक जगह तैनात अफसरों का तबादला होगा’

कोलकाता, 11 फरवरी। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही पद या जिले में तैनात प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के तबादले का निर्देश दिया

- चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले किया बड़ा फैसला।

है। बुधवार को आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। निर्देश के अनुसार, यह आदेश जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, उप-मंडलाधिकारी और अन्य जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू होगा। इसके साथ ही, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) , उप-महानिरीक्षक (डीआईजी), पुलिस अधीक्षक (एसपी) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी स्थानांतरित किया जाएगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी का रुख भारत के प्रति नरम हुआ

जमात के नेता कह रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध बांग्लादेश के लिए बेहद जरूरी हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 11 फरवरी। बांग्लादेश में गुस्से को होने वाले अहम चुनाव से एक दिन पहले, जिसमें नई सरकार चुनी जाएगी और लोकतांत्रिक सरकार का गठन होगा, जमात का एक प्रमुख उम्मीदवार चर्चा में है। ढाका-14 सीट से जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार बैरिस्टर मीर अहमद बिन कासेम अरमान एक हाई-प्रोफाइल चुनाव लड़ रहे हैं। अगस्त 2024 से बांग्लादेश में मुहम्मद युनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है, क्योंकि जुलाई 2024 में हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली पिछली सरकार को हटा दिया गया था। तब से ध्यान इस बात पर है कि चुनाव के बाद बांग्लादेश पर कौन शासन करेगा। इस दौड़ में दो मुख्य दावेदार हैं,

- जमात के एक कद्दावर नेता, मीर अहमद बिन कासेम अरमान, जो ढाका-14 से चुनाव लड़ रहे हैं, का मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ताकतवर नेता संजीदा इस्लाम से है। अरमान ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। हमें साथ मिलकर काम करना होगा।
- बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं और उसके बाद वहाँ निर्वाचित सरकार सत्ता में आएगी। फिलहाल मरहूम खालिदा ज़िया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आगे चल रही है, जिसे उदारवादी छवि के कारण सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है।
- लेकिन, जमात का बदलता रुख संकेत दे रहा है कि अपने भारत विरोधी और पाक समर्थक ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी जमात भारत के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाश रही है।

पहली है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), और दूसरी है, बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी, जो एक कट्टर इस्लामी पार्टी है और समाज के सभी

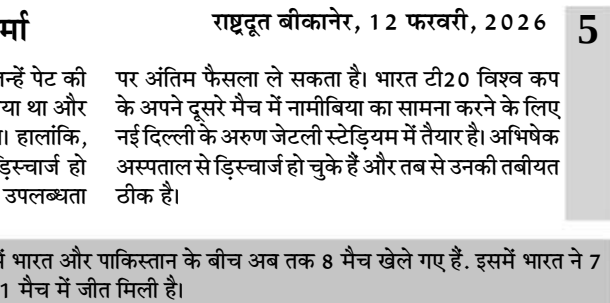
वर्गों के मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। ढाका-14 सीट से जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार अरमान एक हाईप्रोफाइल चुनाव लड़ रहे हैं। वे बांग्लादेश में जबरन गायब किए जाने की घटनाओं के पीड़ित रह चुके हैं। वे बीएनपी की उम्मीदवार संजीदा इस्लाम उर्फ तुलुी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो 'मदर्स कॉल' नाम के संगठन की समन्वयक हैं। यह संगठन जबरन गायब किए गए लोगों के परिवारों द्वारा बनाया गया है। अरमान ने कहा, “हम फिर से तानाशाही नहीं चाहते। मैं जबरन गायब किए जाने का शिकार रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि जनमत संग्रह में 'हाँ' की जीत होगी।” अरमान जमात के बड़े नेताओं में से एक हैं और भारत के साथ मिलकर काम करने की वकालत कर रहे हैं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पैनग्विन रैंडम हाउस को नोटिस

नई दिल्ली, 11 फरवरी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल (विशेष प्रकोष्ठ) ने पैनग्विन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी कर पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक को सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। दूसरी तरफ, दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना

- दिल्ली पुलिस ने नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक को सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराने के मामले में इस पब्लिशिंग हाउस से जवाब तलाब किया है।

प्रमुख की पुस्तक को लेकर दर्ज मामले में और सीक्रेट एक्ट व कॉपी राइट की धाराएं भी जोड़ी हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह नोटिस ऐसे समय में जारी किया गया, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)



वर्ष 23-24 के मुकाबले इस वर्ष बजट का आकार 40 प्रतिशत बढ़ा- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि 24-25 की 93 प्रतिशत तथा 25-26 की 86 प्रतिशत बजट घोषणाओं की क्रियान्विति हो गई

जयपुर, 11 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट 2026-27 तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं-आकांक्षाओं पर खरा उतरने, और सबका साथ, सबका

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वर्ष के बजट में वित्त वर्ष 23-24 की तुलना में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए दोगुनी, चिकित्सा-स्वास्थ्य के लिए 53 प्रतिशत अधिक तथा ग्रीन बजट पर 20.81 प्रतिशत अधिक राशि का प्रावधान किया गया है।

विकास के तीन कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए बनाया गया है।
बुधवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी द्वारा राज्य बजट 2026-27 प्रस्तुत किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बजट में आधारभूत संरचना



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में राज्य बजट 2026-27 प्रस्तुत किए जाने के बाद पत्रकारों से वार्ता की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉ. प्रेमचन्द बैरवा मौजूद थे।

के सुदृढ़ीकरण सहित, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिससे राजस्थान विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में 1441 बजट घोषणाएं की थी, जिनमें से 1246

घोषणाओं (86 प्रतिशत) और वर्ष 2024-25 के बजट की 1277 घोषणाओं में से 1188 घोषणाओं (93 प्रतिशत) की क्रियान्विति की गई है।
उन्होंने कहा कि इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय 53 हजार 978 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो 2023-24 से 2 गुना से अधिक है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32 हजार 526 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, जो 2023-24 से 53 प्रतिशत अधिक है। ग्रीन बजट में 33 हजार 476

करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष से 20.81 प्रतिशत अधिक है। शर्मा ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए बजट में राजस्थान स्टेट टैस्टिंग एजेंसी की घोषणा की गई है।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया सहित, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

‘डॉक्टरों को उपभोक्ता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं में अनुचित व्यापार प्रथाओं या खामियों के लिए समाधान प्राप्त करने का एक तंत्र प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर, 1995 के अपने फैसले में यह माना था कि चिकित्सा सेवाएं भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के धारा 2(1)(0) के तहत “सेवा”

के दायरे में आती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर, 1995 को दिए गए अपने फैसले में यह कहा था: चिकित्सक द्वारा एक मरीज को दी गई सेवा (जब तक कि डॉक्टर किसी मरीज को मुफ्त सेवा न दे रहे हों या व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के तहत सेवा प्रदान न कर रहे हों), परामर्श, निदान और उपचार (चिकित्सीय और शल्य चिकित्सा दोनों) के रूप में दी गई

सेवा, अधिनियम के धारा 2(1)(0) के तहत “सेवा” के दायरे में आएगी।
“यह तथ्य कि चिकित्सा पेशेवर भारतीय चिकित्सा परिषद और/या भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत स्थापित राज्य चिकित्सा परिषदों के अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन होते हैं, उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को (उपभोक्ता संरक्षण) अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं कर सकता।”

पैनग्विन रैंडम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
जब पुस्तक की स्थिति और अनधिकृत संस्करणों के कथित अवैध प्रसार के विरोध में दावे किए जा रहे हैं, जिससे प्रकाशक, पूर्व सेना प्रमुख और वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियां एक व्यापक सार्वजनिक विवाद में शामिल हो गई हैं। पुलिस के अनुसार विशेष प्रकोष्ठ ने नोटिस के माध्यम से प्रकाशक से औपचारिक रूप से संपर्क कर कई सवाल पूछे हैं और उनके विस्तृत जवाब मांगे हैं।

‘राष्ट्रगीत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
इस साल की गणतंत्र दिवस परेड के दौरान, राष्ट्रीय गीत पर आधारित कई झांकियां प्रदर्शित की गई थीं। नए नियमों के तहत, राष्ट्रीय गीत के छह अन्तर्ों का संस्करण, जो 3 मिनट 10 सेकंड तक चलता है, विशेष सरकारी आयोजनों में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके मुकाबले, “राष्ट्रगान” जन गण मन 52 सेकंड का होता है। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि मृदंगम की ध्वनि राष्ट्रीय गान से पहले बजाई जाएगी। जब वन्दे मातरम् और जन गण मन दोनों बजाए जाएंगे, तो राष्ट्रीय गीत पहले बजाया जाएगा। पिछले नवंबर में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कड़ी आलोचना की थी कि उन्होंने “मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए गीत के महत्वपूर्ण अन्तरे हटा दिये थे।” मोदी ने कहा था कि “गीत को टुकड़ों में बांट दिया गया, और इससे देश के विभाजन के बीज बोए गए।” संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय गीत पर चर्चा के दौरान, सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस और कहा-सुनी हुई थी।

‘तीन साल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जिन अधिकारियों ने किसी विशेष जिले या पद पर तीन वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है, उन्हें स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा।

‘आपने भारत माता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कहा गया है कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर के ऊर्जा और तकनीकी उत्पाद खरीदेगा। उन्होंने कहा, “हम मूर्खों की तरह खड़े हैं। हमारा टैरिफ 18 प्रतिशत तक बढ़ गया है... और उनका 16 प्रतिशत से घटकर शून्य हो गया है।”
इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने हस्तक्षेप किया और गांधी से, जो विपक्ष के नेता भी हैं, अमेरिका के साथ हुए सवझौते पर अपने दावों के समर्थन में तथ्य पेश करने को कहा।

रिजिजू ने कहा, “भारत की प्रगति से आपको खुशी नहीं होती। कांग्रेस ने 2014 तक देश को कमजोर किया और अब असंतुष्ट है..”
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को “अब तक का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री” भी बताया।

वृंदावन के होटल में उद्घाटन के दिन ही आग लगी

मथुरा, 11 फरवरी। वृंदावन के रुक्मिणी विहार स्थित नव निर्मित सिद्धि विनायक होटल में बुधवार को उद्घाटन के कुछ ही घंटों बाद भीषण आग लग गई। आग लगते ही होटल के अंदर घना धुआं भर गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में तीन लोग झुलस गए, जबकि करीब 40 लोग होटल के अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर बाद अचानक होटल की ऊपरी मंजिल से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे परिसर में धुएं का गुबार फैल गया। होटल में मौजूद मेहमान और कर्मचारी घबरा गए ?

कई लोग कमरों और गलियारों में फंस गए थे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को खाली कराकर सुरक्षा घेरा बना दिया।

हादसे में होटल मालिक सुभाष अग्रवाल के समथी हरिमोहन के बेटे विनीत की तबियत अधिक बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, आग की चपेट में आकर तीन लोग झुलस गए। घायलों में

- आग के दौरान 40 लोग अंदर फंस गए थे, तीन लोग झुलस गए हैं
- जिलाधिकारी ने बताया कि होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी तथा होटल मालिक के परिवार के तीन लोग झुलस गए।

दो बच्चे कार्तिक और समर तथा एक महिला जिया शामिल हैं। सभी को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। प्रशासन के अनुसार, सभी घायल खतरे से बाहर हैं।

जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि रुक्मिणी विहार स्थित सिद्धि विनायक होटल में उद्घाटन के दिन शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। उन्होंने कहा, इस घटना में होटल मालिक के परिवार के तीन सदस्य झुलस गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें ने तत्परता दिखाते हुए सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। स्थिति अब नियंत्रण में है।

बताया जा रहा है कि होटल में कुल 24 कमरे हैं और बुधवार को ही इसका विधिवत उद्घाटन किया गया था।

एस्टीन से मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के तहत हुई- हरदीप पुरी

नई दिल्ली, 11 फरवरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार (11 फरवरी) को बजट सत्र के दौरान एस्टीन फाइल्स का जिक्र किया, जिसके बाद देश में राजनीति गरमा गई है। इसे लेकर केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि युवा नेता (राहुल गांधी) को पता होना चाहिए कि एस्टीन फाइल्स गलत कामों और आपराधिक मामलों से संबंधित हैं। केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने जेफरी एपस्टीन से मुलाकात की थी, लेकिन यह मुलाकात

■ राहुल गांधी द्वारा जिक्र किये जाने के बाद मंत्री पुरी ने स्पष्ट किया।

अंतरराष्ट्रीय पीस इन्स्टीट्यूट (आईपीआई) के एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहते हुए हुई थी। उन्होंने कहा, साल 2009 में जब मैं अमेरिका में राजदूत था, तब ये मुलाकात हुई। सारी सच्चाई पब्लिक डोमेन में मौजूद है। सार्वजनिक रूप से करीब 3 मिलियन ईमेल हैं। इसके 8 साल बाद मैं मंत्री बना। इस दौरान 3-4 मुलाकातों का जिक्र है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि एस्टीन से उनकी मुलाकात केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के तहत हुई थी।

बांग्लादेश में जमात ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उन्होंने कहा, “भारत और बांग्लादेश एक-दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं और हमें साथ मिलकर काम करना होगा।”
इस बयान को इस रूप में देखा जा रहा है कि जमात, अपने पुराने इतिहास और पहले पाकिस्तान समर्थक रुख के बावजूद, भारत के साथ काम करने की संभावना तलाशने के लिए तैयार हैं। हाल के महीनों में भारत से दूरी बनाकर रखना बांग्लादेश के लिए फायदेमंद नहीं रहा है और यह सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश की ज्यादातर जमीनी सीमा भारत से लगती है। हालांकि बांग्लादेश के जानकारों के अनुसार, बीएनपी अभी आगे मानी जा रही है, लेकिन जमात ने उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की है, जहाँ पहले वह कमजोर थी। पार्टी पर लगा प्रतिबंध

हटने के बाद उसने यह बढ़त हासिल की है और अब वह बहुमत हासिल करने का लक्ष्य रख रही है। जमात के अमीर डॉ. शफीकुर रहमान ने कहा, सिर्फ एक साल पहले मेरी पार्टी को कमजोर माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि हमें बहुत कम सीटें मिलेंगी। आज जमात बहुमत के करीब खड़ी है। यह जनता की इच्छा है। जब जनता एकजुट होती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता।”

रितु तावड़े ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
महापौर तावड़े और उपमहापौर घाड़ी शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करेंगे और राज्य सरकार इस कार्य में उनका पूरा सहयोग करेगी।

TRUE VALUE

खरीदे प्री-ओनर्ड गाड़ी 1 साल तक की वारंटी के साथ, सिर्फ TRUE VALUE पर

CELEBRATING 60Lakh

STORIES OF TRUST

376 क्वालिटी चेक पॉइंट्स

वेरिफाइड कार हिस्ट्री*

1 साल तक की वारंटी और 3 फ्री सर्विस*

यहाँ ऐप डाउनलोड करें

पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएँ यहाँ www.marutisuzukitruevalue.com

BIKANER: NH-89 JAISALMER ROAD, BIKANER, DUDI MOTORS: 8306993375 | OPPOSITE BBS SCHOOL, JAIPUR ROAD, BIKANER, AURIC MOTORS PVT. LTD.: 8875911509, 8003098512 | SRIGANGANAGAR: NEAR KALPATRU WAREHOUSE, NH-15, SRIGANGANAGAR, AURIC MOTORS: 7412059862, 8696543585 | SATIPURA, HANUMANGARH TOWN BYPASS, AURIC MOTORS: 8114425977, 8003995054, 9352166669.

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हल्ला, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय: पलायका हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोरा। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसैनी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसैनी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908